an>

Title: Need to improve telecommunication facilities in Barmer parliamentary constituency, Rajasthan.

कर्नल सोनाराम चौधरी (बाड़मेर) ः मेरा संसदीय क्षेत्र भारत-पाक सीमा से लगभग 250 कि.मी. से ज्यादा सटा क्षेत्र है। यह क्षेत्र पूरा रेगिस्तानी है। इस क्षेत्र की जनता का जीवन स्तर आज भी 100 वर्ष पूर्व की भांति है, क्योंकि क्षेत्र में संचार के साधनों का नितांत अभाव है। इसी कारण इस आधुनिक युग में भी स्थानीय जनता पाषाण युग की तरह जीवन-यापन कर रही है।

बाड़मेर और जैसलमेर जिले में जो मेरे संसदीय क्षेत्र में आते हैं, का क्षेत्रफल 56779 वर्ग कि.मी. है। जिसकी जनसंख्या 3273660 है। 19 ब्लॉक में 581 ग्राम पंचायतें जिनमें 3298 राजस्व ग्राम है। यहां के लोग जीवन-यापन हेतु कृषि, पशुपालन, मजदूरी पर निर्भर है। ज्यादातर प्रदेश में व्यापार एवं मज़दूरी हेतु जाते हैं। इन दोनों जिलों में दूरसंचार के साधनों के अभाव में लोगों को सैंकड़ों कि.मी. की यात्राएं अपने लोगों के हाल-चाल जानने एवं बैंकिंग सुविधाएंÃ¬ प्राप्त करने के लिए करनी पड़ती है जिससे समय एवं धन दोनों की बर्बादी होती है। इन दोनों जिलों में दूरसंचार की व्यवस्था के नाम पर लैंडलाइन के 96 ब्राडबैंड के 74, डब्ल्यू.एल.एल. 71, 2जी के 232, 3जी के 40 और वाई.एम.एक्स के बालोतरा एवं जैसलमेर में मात्र 2 टॉवर की सुविधा है। पूरे क्षेत्र को सूचना प्रौद्योगिकी की सुविधा प्राप्त हो, इस हेतु वर्तमान में 2जी के 181 एवं 3जी के 38 बी.टी.एस. की नितांत आवश्यकता है। विभाग द्वारा 7वें चरण के तहत 46 टॉवर स्वीकृत किये गये हैं। जो जगह और समान के अभाव में संचालित नहीं हो पाये हैं। विडंबना है कि दो पंचायत सीमित मुख्यालय गिडा एवं सेडवा तो ऐसे हैं जहां बी.टी.एस. नहीं है। कवास, रानीगांव, मेवानगर, रावतसर में सिर्फ नेटवर्क की सुविधा नहीं होने के कारण ऑनलाईन कार्य संभव नहीं है। मनरेगा एवं अन्य सरकारी योजनाओं एवं इंटरनेट सुविधाओं से यह क्षेत्र पूर्णतया वंचित है। मेरा संचार मंत्री से आग्रह है कि आधुनिक युग से जोड़ने के लिए प्राथमिकता के तौर पर सीमावर्ती उक्त वंचित क्षेत्र में दूरसंचार की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक स्वीकृतियां एवं संसाधन उपलब्ध करायें ताकि यहां कि पिछड़ी जनता को इस वैज्ञानिक युग का एहसास हो सके।